HCL TECHNOLOGIES LTD.
Corporate Identity Number: L74140DL1991PLC046369
Technology Hub, Special Economic Zone
Plot No : 3A, Sector 126, NOIDA 201 304, UP, India.
T +91 120 6125000 F +91 120 4683030
Registered Office: 806 Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019, India.
www.hcltech.com
www.hcl.com

July 21, 2022

The General Manager
BSE Limited
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400 001

BSE Scrip Code: 532281

The Manager
National Stock Exchange of India Limited
Listing Department
Exchange Plaza
5th Floor, Plot No. C-1, Block-G
Bandra-Kurla Complex, Bandra(E)
Mumbai-400 051

NSE Scrip Code: HCLTECH

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisements published in English and Hindi newspapers, namely Mint All and Hindustan Hindi Delhi Editions, respectively on July 21, 2022.

The above information is also available on the website of the Company at www.hcltech.com.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **HCL Technologies Limited**

Manish Anand

Manish Anand
Company Secretary

Encl:a/a

मेरठ के हस्तिनापुर विस से विधायक दिनेश खटीक ने 9 जून को गंगानगर थाने में दी थी चेतावनी, 19 जुलाई को दिया त्यागपत्र

थाने से उठा विवाद मंत्री के इस्तीफे तक जा पहुंचा

इस्तीफे पर सियासत

मेरठ, मुख्य संवाददाता। जलशक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक का गंगानगर थाने में एक मुकदमे से शुरू हुआ विवाद इस्तीफे तक पहुंच गया। 9 जून की रात मुकदमा दर्ज न होने पर उन्होंने इस्तीफे की चेतावनी दी थी। 19 जुलाई को उपेक्षा और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राज्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया।

पूरे मामले की शुरुआत 4 जून को हुई थी। उनके एक करीबी टेंट कारोबारी कोमल की दो पुलिसकर्मियों से कहासुनी हो गई थी। कोमल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो 9 जून को राज्यमंत्री ने गंगानगर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। इंस्पेक्टर ने साफ मना कर दिया। मंत्री ने विरोध में धरना दिया और इस्तीफे की धमकी दे डाली।

मामला तत्कालीन एसएसपी प्रभाकर चौधरी तक पहुंचा लेकिन बात नहीं बनी। 10 जून को इस्तीफे की घोषणा के लिए उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया को बुलाया। भनक लगते ही भाजपा जिलाध्यक्ष विमल शर्मा पहुंच गए। कहा जाता है कि उस सयम मान मनौव्वल के बाद इस्तीफे की घोषणा टल गई। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली लेकिन क्रास रिपोर्ट भी हो गई। यहां भी मंत्री की किरकिरी हुई।

दिनेश खटीक। •

संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ा है दिनेश खटीक का परिवार

जलशक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक(45) और उनका परिवार शुरू से संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा है। मेरठ के फलावदा के मूल निवासी दिनेश खटीक का राजनीतिक सफर आरएसएस से ही प्रारंभ हुआ। 1994 में फलावदा में संघ के खंड कार्यवाह बने। 2006 में उन्हें विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल में भी काम करने का मौका मिला। 2007 में भाजपा के जिला मंत्री बने। 2010 में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बनाये गए। 2013 में वे भाजपा के जिला महामंत्री भी बने। साथ ही अनुसूचित मोर्चा में भी जिम्मेदारी मिली। 2017 में भाजपा ने पहली बार हस्तिनापुर से टिकट दिया और विधायक चुने गए। 26 सितंबर 2021 में उन्हें योगी सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। 2022 में भाजपा से दूसरी बार टिकट मिला। वह हस्तिनापुर से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए।

हमारी बात नहीं सुनते अधिकारी: दिनेश

दिनेश खटीक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजे पत्र में आरोप लगाया कि विभाग में मेरे आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं होती और न ही मुझे किसी बैठक की सूचना दी जाती है। विभागीय अधिकारी सिर्फ गाड़ी उपलब्ध करा देना ही राज्यमंत्री का अधिकार समझते हैं। विभाग में तबादलों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। दलित जाति का मंत्री होने के कारण विभाग में मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है।

राज्यपाल की जगह पहले गृहमंत्री को भेजा इस्तीफा

खटीक ने कहा कि इस संबंध में जब सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग से बात की तो उन्होंने पूरी बात सुने बिना ही फोन काट दिया। इन्हीं सब बातों से आहत होकर त्यागपत्र देने की बात उन्होंने वायरल पत्र में कही है। हालांकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल की जगह पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को इस्तीफे का पत्र भेजे जाने को दबाव की राजनीति का हिस्सा बताया जा रहा है।

इस्तीफ में ये लगाए आरोप

- दलित मंत्री होने के नाते मेरे आदेश पर नहीं होती कोई कार्यवाही
- विभागीय बैठकों और योजनाओं की नहीं दी जाती जानकारी
- विभाग में स्थानांतरण सत्र में किया गया भ्रष्टाचार
- मांगने पर भी विभागाध्यक्ष और प्रमुख सचिव ने नहीं दी तबादलों की जानकारी
- विभाग में कोई काम नहीं मिला इसलिए नहीं मिलता मेरे पत्रों का जवाब

नाटकीय ढंग से शुरू हुआ घटनाक्रम : मेरठ की हस्तिनापुर सीट से विधायक दिनेश खटीक जलशक्ति राज्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इसके बाद पूरे मंत्रिमंडल की एक बैठक अलग से दोपहर 12 बजे बुलाई गई। इसमें सभी कैबिनेट, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्यमंत्रियों को बुलाया गया। दिनेश खटीक इस बैठक में पहुंचे ही नहीं। सूत्रों का कहना है कि एक दिन पहले वह संगठन मंत्री सुनील बंसल से भी मिले थे। इसके बाद मंगलवार को वह राजभवन गए और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा दे दिया।

दिल्ली दरबार में यूपी के परेशान मंत्रियों का मामला

नईदिल्ली, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को लेकर मंत्रियों की नाराजगी और परेशानी का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। राज्य सरकार के दो मंत्रियों दिनेश खटीक और जतिन प्रसाद ने अपनी अपनी बात भी पहुंचाई है। सूत्रों के अनुसार खटीक का गृह मंत्री अमित शाह के नाम लिखा इस्तीफा वाला पत्र सोशल मीडिया पर आने के बाद पार्टी नेतृत्व ने इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है, लेकिन स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए समझाइश जरूर दी है।

सूत्रों के अनुसार अपने ओएसडी के भ्रष्टाचार के मामले में उलझे जतिन प्रसाद ने भी केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाई है। मंत्री दिनेश खटीक भी दिल्ली में सक्रिय रहे। इन मामलों में केंद्रीय नेतृत्व ने सीधे तौर पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन संकेत दिए हैं कि जल्द ही वहां पर सब कुछ ठीक-ठाक कर लिया जाएगा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने खटीक के इस्तीफे की चिट्ठी गृह मंत्री को भेजे जाने के मामले पर कहा कि इस्तीफा मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजा जाता है। इसलिये इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कहीं कुछ नाराजगी होती है उसे दूर कर लिया जाता है।

भाजपा सरकार में चल रहा है भ्रष्टाचार उद्योग : कांग्रेस

कांग्रेस ने मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की दुहाई देती थी, उनके मंत्री दिनेश खटीक का इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि सरकार में सिर्फ एक उद्योग चल रहा है। वह है भ्रष्टाचार उद्योग। मीडिया संयोजक अंशु अवस्थी ने कहा कि दलितों को लेकर जो झूठे प्रेम का दिखावा भाजपा करती थी, मंत्री ने अपने इस्तीफे में उसकी कलई खोल दी है। कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि भाजपा सरकार में दलितों का अपमान हो रहा है।

मंत्री जितिन प्रसाद ने किया नाराजगी से इनकार

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद बुधवार को तबादला विवाद का पटाक्षेप करने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह बिल्कुल नाराज नहीं हैं। प्रदेश सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। जो भी गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा भी की।

पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत कर खुद के बारे में चल रही अटकलों खारिज किया। उन्होंने न्यूज एजेंसी के एक ट्वीट को री-ट्वीट भी किया। इसमें उन्होंने कहा है-'पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर विभाग में अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी ही। एक निष्पक्ष जांच होगी और जहां भी गड़बड़ी है, वहां कार्रवाई होगी और बदलाव भी होगा। इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है।' इससे पहले माना जा रहा था कि वह दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं।

भाजपा बताए अब विद्रोह की किसकी बारी: अखिलेश

लखनऊ, विशेष संवाददाता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार में तबादलों को लेकर मची रार पर बुधवार को करारा वार किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर केवल दिनेश खटीक के दलित होने के कारण उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया। वहीं, लगातार स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी और जलशक्ति मंत्रालय में हो रहे विवाद पर टिप्पणी की।

अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं हो परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अच्छा है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। भाजपा को बताना चाहिए कि अब विद्रोह करने की किसकी बारी है।

दलित मंत्री की उपेक्षा दुर्भाग्यपूर्ण: बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी भाजपा सरकार में दलित मंत्री की उपेक्षा दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने बुधवार को खटीक मामले में ट्वीट कर कहा कि इससे सरकार की जातिवादी मानसिकता का साफ पता चलता है।

आमने-सामने

सपा प्रमुख साजिश की जगह अपनी पार्टी बचाएं : केशव

लखनऊ, विशेष संवाददाता। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा प्रदेश सरकार को लेकर किए गए ट्वीट पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों को केवल वोट बैंक समझने वाले सपाई, बसपाई, कांग्रेसी भाजपा को ज्ञान नहीं दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए डबल इंजन सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख साजिश करने की जगह अपनी पार्टी को बचाएं।

खटीक से रोज बात होती है, वह नाराज नहीं : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी अखिलेश पर पलटवार किया है। स्वतंत्र देव ने कहा कि उनकी जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक से रोजाना बातचीत होती रहती है, वह नाराज नहीं हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है।

मंकीपॉक्स के बाद मारबुर्ग वायरस ने बढ़ाई चिंता

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। विश्व भर में कोरोना के बाद कई देशों में मंकीपॉक्स का खतरा अभी बरकरार है। हाल के दिनों में कई देशों में मंकीपॉक्स के मामलों में वृद्धि भी दर्ज की गई है, लेकिन अब कोरोना और मंकीपॉक्स के साथ ही एक नए और बेहद खतरनाक वायरस ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इस नए वायरस का नाम है, मारबुर्ग। हालांकि राहत की बात यह है कि इस वायरस के मामले अभी कुछ अफीक्री देशों में ही आए हैं। रक्तस्रावी बुखार संबंधी मारबुर्ग को दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस माना जाता है।

कोई दवा या टीका नहीं : विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, अब तक सामने आए मामलों के आधार पर मारबुर्ग से होने वाली मृत्यु दर 80 फीसदी से अधिक है। घाना से पहले सितंबर 2021 में गिनी में वायरस का एक मामला सामने आया था। कॉन्गो, दक्षिण अफ्रीका व युगांडा में भी मारबुर्ग के मामले सामने आ चुके हैं। वायरस से लड़ने के लिए फिलहाल कोई दवा या टीका नहीं बना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मारबुर्ग, इबोला जितना खतरनाक है। इससे संक्रमित होने पर इंसान को तेज बुखार, डायरिया, उल्टी और सिरदर्द होने लगता है।

चमगादड़ों, अन्य जानवरों से इंसानों में फैलाव : इस संक्रमण पर लगातार अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि मारबुर्ग वायरस चमगादड़ों समेत अन्य जानवरों से इंसान में फैल सकता है। इसके बाद लार या छींक से बाकी लोगों तक पहुंच सकता है। घाना में कई मामलें सामने आने के बाद वहां लोगों को सलाह दी गई है कि वे चमगादड़ों की गुफाओं से दूर रहें और खाने से पूर्व मांस को ठीक से धुलकर अच्छी तरह पकाएं।

ऐसे हुआ नामकरण

1967 में सबसे पहले इस वायरस का पता जर्मनी के मारबुर्ग शहर में चला। उसी आधार पर इसे मारबुर्ग कहा गया। अफ्रीका से लाए गए कुछ ग्रीन बंदरों से यह वायरस शहर में फैला। कुछ ही समय में यह जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट और बेलग्रेड पहुंच गया। साल 1988 से अब तक इस वायरस से पीड़ित अधिकांश रोगियों की मौत हो गई।

मंकीपॉक्स पर केरल में एसओपी जारी

केरल में मंकीपॉक्स के दो मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी। इसके तहत संक्रमित और लक्षण वाले लोगों के लिए पृथक रहने, नमूने एकत्रित करने और उपचार के लिए जानकारी दी गई है।

अपनी रफ्तार से चकित करने भारत आ रहा चीता

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता जल्द भारत में भी दिखेगा। देश में विलुप्त हो चुके चीतों को वापस लाने के लिए भारत ने नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अगले महीने नामीबिया से आठ चीते भारत लाए जाएंगे, जिनमें चार नर और चार मादा होंगे।

ये चीते मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान पहुंचाए जाएंगे। भारत यात्रा पर आई नामीबिया की उप-राष्ट्रपति नानगली म्बुम्बा और केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने बुधवार को इस बाबत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत भारतीय वन्य जीव महकमे के कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जबकि भारत वन्य जीव संरक्षण के दूसरे क्षेत्रों में नामीबिया को मदद करेगा।

दक्षिण अफ्रीका से भी लाए जाएंगे चीते: पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि नामीबिया के अलावा दक्षिण अफ्रीका से भी चीते लाए जाएंगे। अगले पांच साल में अफ्रीकी देशों से कुल 30 चीते लाने की योजना सरकार की है।

1952 में चीतों के विलुप्त होने की घोषणा हुइ

1. मंत्रालय के अनुसार, आजादी से पूर्व देश में चीतों की खासी तादाद थी, लेकिन शिकार के कारण इनकी आबादी घटती गई।
2. 1948 में छत्तीसगढ़ के कोरया जिले में चार चीते मारे गए थे। इसके बाद 1952 में देश में चीतों के विलुप्त होने की घोषणा कर दी गई।

'मोदी को दंगों में फंसाना चाहती थीं सीतलवाड़'

दावा

अहमदाबाद, एजेंसी। गुजरात पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने अदालत में कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ 2002 में राज्य में हुए दंगों के मामलों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को फंसाने की साजिश में शामिल थीं। एसआईटी ने बुधवार को यह भी आरोप लगाया कि सीतलवाड़ ने पीड़ितों के नाम पर धन जमा किए और उक्त राशि का इस्तेमाल भाजपा की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों में किया।

सीतलवाड़ को अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने पिछले महीने पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आर. बी. श्रीकुमार और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट के साथ गिरफ्तार किया था। इन पर 2002 के दंगों के आरोप में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए झूठे सबूत गढ़ने का आरोप है। सीतलवाड़ इस समय जेल में हैं और उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दी है। एसआईटी ने जमानत अर्जी का विरोध किया है।

सीतलवाड़ की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मितेश अमीन ने अहमदाबाद में सत्र न्यायाधीश डी. डी. ठक्कर की अदालत में कहा कि वह तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को दंगों के मामलों में आरोपियों के तौर पर फंसाने की वृहद षड्यंत्र का हिस्सा थीं।

तैयारी | ई-संजीवनी ओपीडी की तर्ज पर शुरू होगी सुविधा, मरीज घर बैठे डॉक्टरों से निःशुल्क सलाह ले सकेंगे

मानसिक रोगियों के लिए ऑनलाइन ओपीडी जल्द

■ **मदन जैड़ा**

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का मसौदा तैयार कर लिया है। इसके तहत ई-संजीवनी ओपीडी की तर्ज पर मानसिक रोगियों के लिए भी जल्द ऑनलाइन ओपीडी सेवाएं शुरू होंगी। देश में मानसिक रोगियों की बढ़ती संख्या और डॉक्टरों की कमी के बीच यह कार्यक्रम दूरदराज के क्षेत्रों में मानसिक रोगियों के उपचार में महत्वपूर्ण साबित होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब इसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय के बेंगलुरु स्थिति संस्थान निम्हंस को नोडल एजेंसी बनाया गया है। निम्हंस से देश भर के 17 और मानसिक रोग अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है। इसके बाद ई-संजीवनी की तर्ज पर ऑनलाइन ओपीडी सेवा शुरू की जाएगी। यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क होगी।

- राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का मसौदा तैयार हुआ
- कार्यक्रम दूरदराज में मानसिक रोगियों के लिए अहम साबित होगा

ई-संजीवनी की शुरुआत कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सामान्य बीमारियों के लिए की थी, जिसमें अब तक सवा करोड़ से अधिक मरीजों को ऑनलाइन देखा जा चुका है। इसमें पहले रोगी को ऑनलाइन पंजीकरण करना होता था तथा ओटीपी के पुष्टिकरण के बाद एक टोकन प्रदान किया जाता है। इसके बाद मरीज एक ऑनलाइन वेटिंग रूम में प्रवेश करता है और कुछ ही मिनटों में डॉक्टरों से संपर्क करता है। डॉक्टर से परामर्श के बाद उसे पर्ची डाउनलोड करनी होती है, जिससे वह दवा खरीदता है। इसी मॉडल को मानसिक रोग स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए लागू किया जा रहा है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम का मसौदा तैयार है तथा कुछ आवश्यक सुधारों के बाद इसे लागू किया जाएगा। यह भी कोशिश की जा रही है कि पहले सुरक्षा बलों में इस योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाए और उसके बाद देश भर में।

farnazfever

देश 30s

साधु ने आत्मदाह का किया प्रयास

जयपुर। राजस्थान के डीग क्षेत्र में खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर चल रहे साधुओं के आंदोलन के दौरान एक साधु ने बुधवार को आत्मदाह का प्रयास किया। अधिकारियों के अनुसार, साधु को गंभीर अवस्था में जयपुर भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि धरनास्थल से दूर खड़े एक साधु विजय दत्त ने अचानक ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर खुद को आग लगा ली। पुलिस वाले उसे बचाने दौड़े और आग बुझाकर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

अग्निपथ योजना पर 25 अगस्त को सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह सशस्त्र बलों में भर्ती संबंधी केन्द्र की 'अग्निपथ' योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगा, क्योंकि उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा यहां स्थानान्तरित की गई याचिकाओं से जुड़े दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि उच्चतम अदालत ने 19 जुलाई को योजना को चुनौती वाली याचिकाओं को स्थानान्तरित कर दिया था।

जेईई मेन का दूसरा सत्र 25 जुलाई से शुरू होगा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने बुधवार को घोषणा की है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)-मेन स्थगित कर दी गई है। अब यह 21 जुलाई की बजाय 25 जुलाई से शुरू होगी। एनटीए ने हालांकि इस महत्वपूर्ण परीक्षा को स्थगित करने का कारण नहीं बताया। एनटीए ने कहा,'जेईई-मेन का दूसरा सत्र 25 जुलाई से शुरू होगा जिसमें करीब 500 शहरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 6.29 लाख छात्र परीक्षा देंगे।

भाजपा दो, कांग्रेस एक सीट जीती

भोपाल। मध्य प्रदेश में पांच नगर निगमों में से तीन पर आए महापौर पद के परिणामों में से दो सीटें भाजपा ने निकाली है, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है। एक अधिकारी ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि महापौर चुनाव में रीवा में कांग्रेस के उम्मीदवार अजय मिश्रा बाबा ने भाजपा उम्मीदवार प्रमोद व्यास को 10,282 मतों के अंतर से पराजित किया। इससे पहले यह सीट भाजपा के पास थी। देवास में भाजपा की उम्मीदवार गीता अग्रवाल ने कांग्रेस की विनोदिनी व्यास को 45,884 मतों के अंतर से हराया। वहीं, रतलाम महापौर पद भी भाजपा ने अपने पास बरकरार रखा है।

पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ईडी हिरासत में

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू अदालत ने बुधवार को एनएसई को-लोकेशन घोटाले से जुडे धनशोधन मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को नौ दिन की प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को फोन टैपिंग और जासूसी से जुड़े धनशोधन मामले में संजय पांडे को मुंबई से गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा की अदालत ने ईडी के आग्रह पर संजय पांडे को रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने पांडे को 14 दिन की हिरासत मांगी थी।

एमएसपी समिति पर भगवंत मान ने केंद्र को घेरा

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर गठित समिति में राज्य को प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने के लिए बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने ट्वीट किया, किसानों से किए गए वादे के विपरीत, एमएसपी समिति में पंजाब को प्रतिनिधित्व नहीं देने के केंद्र के निर्णय की मैं निंदा करता हूं। पंजाब के किसान पहले ही फसल चक्र और कर्ज में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी हमारा कानूनी अधिकार है।

बॉलीवुड माफिया कर रहे परेशान : तनुश्री दत्ता

मुंबई। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने आरोप लगाया है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बॉलीवुड माफिया और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। तनुश्री ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर कहा कि उन्हें व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। बिना किसी का नाम लिए तनुश्री ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि 'मीटू' दोषी और एनजीओ जिनका मैंने खुलासा किया है, वह इस सब के पीछे हैं, वरना मुझे इस तरह निशाना बनाकर क्यों परेशान किया जाएगा?

नवलखा को जेल में फोन सुविधा नहीं दे सकते

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय से बुधवार को कहा कि वह सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को जेल से फोन करने की अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि वह आतंकवाद के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने इस साल 25 मार्च को ऐसी सुविधाओं पर रोक लगा दी थी। नवी मुंबई की तलोजा जेल सहित विभिन्न जेलों में कैदियों के लिए फोन कॉल करने के वास्ते एक 'कॉइन बॉक्स' सुविधा उपलब्ध है, जहां नवलखा और मामले के अन्य आरोपी विचाराधीन कैदी के रूप में बंद हैं।

एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड

कार्पोरेट पहचान संख्या : L74140DL1991PLC046369
पंजीकृत कार्यालय : 806, सिद्धार्थ, 96, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019
कारपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 3ए, सेक्टर–126, नोएडा– 201304, उ.प्र., भारत टेलीफोन : +91 11 26436336
वेबसाइट : www.hcltech.com; ई–मेल आईडी: investors@hcl.com

विडियों कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") एवं अन्य दृश्य–श्रव्य ("ओएवीएम') माध्यमों के द्वारा आयोजित होने वाली 30वीं वार्षिक सामान्य बैठक

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 30वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 16 अगस्त, 2022 को प्रातः 11:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर "वीसी"/"ओवीएम" के द्वारा आयोजित की जाएगी ताकि बैठक को आयोजित करने के लिए भेजी जा रही सूचना में निर्धारित कामकाज को पूरा किया जा सके।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र सं. 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 एवं अन्य परिपत्रों ("एमसीए परिपत्रों") के साथ में पठित, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम को आयोजित करने की अनुमति दे दी है। एमसीए परिपत्रों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों और इसके अधीन दिए गए नियमों के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों की एजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 ("सेबी परिपत्र") और एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में, सदस्यों को एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (2021–22) के साथ कम्पनी के एजीएम का नोटिस उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा रहा है जिनके ई–मेल पते कम्पनी/डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत है।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट (2021–22) कम्पनी की वेबसाइट www.hcltech.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा ई–मतदान (दूरस्थ ई–मतदान सहित) सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी, नेशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध करवाएं जाएंगे।

एजीएम में रिमोट ई–मतदान/ई–मतदान के माध्यम से वोट डालने का तरीका

क) सदस्यों के पास ई–मतदान (दूरस्थ ई–मतदान सहित) के माध्यम से एजीएम में निर्धारित किए गए व्यवसायों पर अपना मतदान देने का अवसर होगा। डिमैटिरिलाइज्ड / भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले सदस्यों को ई–मतदान (दूरस्थ ई–मतदान सहित) को विधि, एजीएम के नोटिस में प्रदान की जाएगी।

ख) ई–मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में उपस्थित होने वाले वे सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से, एजीएम के दौरान ई–मतदान प्रणाली द्वारा मतदान देने के लिए पात्र होंगे जिन्होंने दूरस्थ ई–मतदान अवधि के दौरान प्रस्तावों पर अपना मतदान नहीं दिया है और ऐसा करने से वे वर्जित नहीं है।

ग) ई–मतदान (दूरस्थ ई–मतदान सहित) के माध्यम से मतदान करने के लिए लॉग–इन प्राथमिकताएं (क्रेडेंशियल्स), सदस्यों को ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। जिन सदस्यों को ई–मेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ई–मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत नहीं है, वे निम्नलिखित निर्देशों का पालन करते हुए अपनी लॉग–इन प्रमाणिकताएं उत्पन्न कर सकते है।

ई–मेल पतों को पंजीकरण / अद्यतन करने का तरीका

जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पतों को कम्पनी या उनके डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि निम्नलिखित लिंक : https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html के माध्यम से तथा उसमें दिए गए अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करके, एजीएम के नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट (2021–22) को प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु उसे अस्थायी रूप से पंजीकृत करें:

ई–मेल पतों के स्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्य कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:–

भौतिक रूप से रखे शेयरों के लिए	1. निम्नलिखित लिंक पर जाएं https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html 2. कम्पनी के नाम यानी एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड को चुनें। 3. फोलियों नं., शेयरधारक का नाम, सर्टिफिकेट नं. पैन, मोबाइल नम्बर, ई–मेल–आईडी का उल्लेख करें तथा साथ में अपने पैन कार्ड/आधार/वैध पासपोर्ट आदि की स्व–साक्ष्यांकित प्रति दें।
डिमैटिरियलाइज्ड रूप में रखे शेयरों के लिए	इलेक्ट्रॉनिक विधि में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि अपने ई–मेल पतों, पैन व बैंक खाता विवरणों को उस डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत/नवीकृत करवाएं जहॉं उनके संबंधित डिमैट खाते है।

यदि ई–मेल पते की पंजीकरण प्रक्रिया में कोई भी प्रश्न है, तो सदस्य कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट से rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर सम्पर्क कर सकते है।

कृते एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड

दिनांक : जूलाई 20, 2022
स्थान : नोएडा (यू.पी.)

मनीष आनंद
कम्पनी सचिव

Sterlite eyes $500 mn to set up transmission infra

The company is in discussions with pension and sovereign wealth funds

Swaraj Singh Dhanjal
swaraj.d@livemint.com
MUMBAI

Sterlite Power has a portfolio of 28 projects covering approximately 13,950 circuit kms of transmission lines in India and Brazil. MINT

Sterlite Power, one of the biggest private developers of power transmission lines in India, is in discussions with pension funds and sovereign wealth funds to raise $500 million to $1 billion, said two people aware of the development.

Sterlite Power has a portfolio of 28 projects covering approximately 13,950 circuit kms of transmission lines in India and Brazil. It also has a portfolio of high-performance power conductors, extra high voltage cables and optical ground wires.

"Sterlite has been meeting investors to raise funds. It will look to raise between $500 million and $1 billion, which will help them bid for projects and grow their portfolio both in India and in Brazil," said one of the two people seeking anonymity.

In December 2020, Sterlite Power and investment manager AMP Capital had announced plans to set up four power transmission projects worth $1 billion, with both parties agreeing to invest $150 million each.

According to the second person, foreign investors, especially patient capital investors such as pensions and sovereign funds, are keen to invest in transmission projects in India as the asset class has several advantages over other infrastructure projects.

"Transmission lines have a longer concession tenure of 35 years compared to roads or renewables where you have 20-25 years concessions. This makes the sector more attractive to long-term investors such as pension funds and sovereign funds. Additionally, unlike power generation, where you have payment issues with state discoms, the transmission sector doesn't have a similar challenge considering that the counterparty is PowerGrid Corp," he said.

POWERING GROWTH

IN 2020, Sterlite Power & AMP Capital had announced plans to set up four projects worth $1 bn

FOREIGN investors, especially patient capital investors, are keen to invest in transmission works

LONG concession tenure of 35 years makes the sector more attractive to long-term investors

"There are enough investment opportunities in the transmission sector in India as only a few private sector players are active in the space," he added.

Most transmission assets in the private sector are held either by Sterlite or Adani Transmission. A few other smaller companies own one or two assets. Adani Transmission has a portfolio of more than 18,500 circuit km of transmission lines. "Given the sector's attractiveness and few investment opportunities, Sterlite's fundraising plans are likely to see strong interest," he added.

Queries emailed to Sterlite Power did not elicit any response.

Sterlite Power had sponsored IndiGrid, the country's first power sector Infrastructure Investment Trust (InvIT), which went public in 2017. In 2019, private equity investor KKR and Singapore's sovereign wealth fund GIC invested over ₹2,000 crore to pick up a 42% stake in Indigrid. Earlier this year Sterlite exited from the InvIT.

IndusInd Bank's Q1 net profit up 61%

Staff Writer
feedback@livemint.com
MUMBAI

IndusInd Bank on Wednesday reported June quarter net profit at ₹1,631 crore rising 61% from the year-ago on the back of lower provisions and higher net interest income.

The private sector lender's provisions stood at ₹1,251 crore in the three months to June, down 30% from the year ago. Its net interest income (NII), the difference between interest earned and expended, was at ₹4,125 crore in Q1 FY23, up 16% from the year ago, while its net interest margin, an important measure of profitability, was up by 15 basis points (bps) year-on-year to 4.21%, and one bps sequentially.

Sumant Kathpalia, managing director and chief executive, IndusInd, said Q1 witnessed turbulent operating environment with amid higher inflation, reversal of an accommodative monetary policy and the Russia-Ukraine war. "First quarter of a financial year is a seasonally weak quarter for some businesses. The bank has nevertheless focussed on delivering on its strategic ambitions," he added.

The bank posted 18% loan growth to ₹2.48 trillion as on 30 June and its deposits rose 13% from the year-ago to ₹3.03 trillion

The bank posted 18% loan growth to ₹2.48 trillion as on 30 June. Its deposits rose 13% from the year-ago to ₹3.03 trillion in the same period. "We have always said we will grow (our loanbook) at 16-18% compound annual growth rate. This year, we will grow at about 20% because we are catching up on last year, when we grew at 12%," he said.

The bank witnessed a slight deterioration in asset quality compared to the March quarter. Its gross bad loans stood at 2.35% of its total advances, up 8 bps from 31 March.

However, compared to the corresponding quarter of last year, IndusInd Bank's gross bad loan ratio was down 53 bps.

Its capital adequacy ratio as per Basel III guidelines grew to 18.14% as on 30 June, as compared to 17.57% in the year ago.

IndusInd Bank shares on the BSE closed at ₹878.9 on Wednesday, up 1.2% from its previous close.

ITC expects ₹5 trillion in FMCG sales by 2030

Staff Writer
feedback@livemint.com
NEW DELHI

ITC Ltd on Wednesday said its consumer goods business, comprising packaged flour, chips, biscuits and soaps, has substantial headroom to grow, with the FMCG market expected to reach ₹5 trillion by 2030.

In FY22, its FMCG businesses, excluding cigarettes, recorded ₹15,994.49 crore in revenue up 8.6% from the year earlier. ITC's packaged goods sel under the Aashirvaad, Sunfeast, Bingo, Savlon, and Yippee brands, among others.

"ITC is now the largest incubator of FMCG brands in India, anchoring competitive and inclusive value chain in wheat, fruits, vegetables, dairy, aqua and forestry, among others, which empower millions of farmers," ITC chairman and managing director Sanjiv Puri told shareholders at the company's 111th annual general meeting. In FY22, ITC launched 110 products and made several acquisitions over the last two years, including investments in direct-to-consumer brands.

ITC competes with the likes of Hindustan Unilever, Nestle and Britannia Industries.

APPEAL

With support of fellow residents of Delhi and the inspirational guidance of Lt. Governor, Shri V.K. Saxena, we at MCD are striving to provide better civic amenities in the National Capital.

In this direction, efforts are being made to scientifically flatten the garbage mounds in Delhi. This would require proactive cooperation on part of the people of Delhi. As you all know, the entire garbage of Delhi is dumped into the Ghazipur, Okhla and Bhalaswa sanitary landfill sites. Due to continuous dumping for the last 35-40 years, heaps of garbage at these landfill sites have turned into garbage 'mountains' of 50 to 60 metres height, containing 280 lakh tonnes of garbage.

All units of Municipal Corporation are involved in reducing the height of these unseemly mounds by undertaking the disposal of garbage accumulated there. In this process, while on the one hand, we are using plastic waste in Waste to Energy Plant to generate electricity, on the other hand, we are segregating Construction & Demolition Waste (C&D Waste) and Inert Waste and turning them useful products which can be used to fill low-lying areas and pot-holes, make foundation of a building, road construction, inter-locking blocks, etc.

I appeal to the residents of Delhi and the National Capital Region, Builders, Road Developers, Contractors and related Government Agencies to optimally use the C&D Waste and Inert material for their construction activities and become our partners in addressing this festering problem affecting the National Capital.

It has been decided that any department, agency, individual or contractor, etc. can take the available C&D and Inert material for their use themselves, free of cost from these three landfill sites. In this regard, you can take permission of Municipal Corporation of Delhi by writing to **ceprojectmcd@gmail.com** giving details of your requirement. Shri Sanjay Hingorani, Nodal Officer can also be contacted on **Phone No.: 011-23226903; 9717788196 (WhatsApp)**, for any assistance.

Commissioner
R.O. No.17/DPI/MCD/2022-23 **Municipal Corporation of Delhi**
LET US COME TOGETHER AND FREE DELHI OF GARBAGE MOUNDS.

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ओमेगा–1, (पी–2), ग्रेटर नौएडा
Toll Free No. 18001808296 वेबसाइट: www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांक: वाई.ई.ए./भूलेख/तह0–वी0एम0/710/2022 दिनांक: 19.07.2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नलिखित भूमि का यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर वितरण किया जाना प्रस्तावित है:–

चिन्हित पॉकेट का विवरण	पॉकेट के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम/गाटा	
प्रयोजन	ग्राम	गाटा संख्या
सैक्टर–18	उस्मानपुर	397, 427, 458म, 459, 533, 536, 547, 551, 552, 553, 554, 559, 560, 561, 562, 592, 608, 613, 631, 645, 655, 667, 669, 671, 676, 683, 687, 688

1. यदि मूल काश्तकार की मृत्यु हो गई है तो उनके वारिसानों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने व मूल काश्तकार का मृत्यु प्रमाण–पत्र, वारिसान प्रमाण–पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, हिस्सा दर्ज खतौनी की नकल, परिवार सदस्यता प्रमाण व शपथ–पत्र, अनुबंध पत्र, पहचान पत्र/आधार कार्ड व ब्यान आदि जमा करने पर RTGS/NEFT के माध्यम से वारिसानों के नाम Transfer किया जायेगा।
2. वर्तमान में काश्तकारों को RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। काश्तकार सुसंगत पहचान पत्र जैसे–आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि व अन्य आवश्यक अभिलेख जैसे – शपथ–पत्र, अनुबंध पत्र आदि तैयार करा लें। बैंक खाते व प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेखों में काश्तकार का नाम एक समान होना चाहिए अन्यथा RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान में अड़चन आ सकती है। अतः बैंक खाते में नाम भी सही करा ले ताकि भुगतान में कोई अड़चन न आवें। तालिका में शामिल गाटा संख्या के काश्तकार उक्त अभिलेख 15 दिन से पूर्व ही प्राधिकरण में जमा करा दें ताकि उनकी समय से जाँच हो सके तथा भौतिक कब्जा सत्यापन उपरांत उनका भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से यथाशीघ्र कराया जा सके।
3. भूमि के अतिरिक्त प्रतिकर वितरण किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दर सी0आर0 सेल/तहसीलदार, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

विशेष कार्यधिकारी

HCL TECHNOLOGIES LIMITED
Corporate Identity Number: L74140DL1991PLC046369
Registered Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi -110019
Corporate Office: Plot No. 3A, Sector 126, Noida - 201304, UP, India
Telephone: +91 11 26436336
Website: www.hcltech.com; E-mail ID: investors@hcl.com

30TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM")

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the members of HCL Technologies Limited (the "Company") will be held on Tuesday, August 16, 2022 at 11:00 A.M. (IST) through VC / OAVM to transact businesses, as set forth in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM.

Pursuant to the General Circular no. 2/ 2022 dated May 5, 2022 and other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), companies are allowed to convene their AGMs through VC / OAVM, without the physical presence of the members at a common venue. In compliance with the MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the AGM of the members of the Company will be held through VC/OAVM.

The MCA Circulars read with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular no. SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 ("SEBI Circular"), has dispensed with the requirement of sending the physical copies of the AGM Notice and Annual Report to the members. Accordingly, the Notice of the AGM along with the Annual Report (2021-22) of the Company is being sent only through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories Participants.

Members may note that Notice of the AGM and the Annual Report (2021-22) will also be made available on the website of the Company at www.hcltech.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively as well as on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com, the agency appointed for facilitating e-voting (including remote e-voting) for the AGM.

Manner to cast vote(s) through remote e-voting / e-voting at the AGM

a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through e-voting (including remote e-voting). The manner of e-voting (including remote e-voting) by members holding shares in dematerialized / physical form shall be provided in the Notice of the AGM.
b) The facility of e-voting will also be made available at the AGM and members attending the AGM through VC / OAVM, who have not cast their vote(s) on the resolution(s) during the remote e-voting period and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
a) The log-in credentials to cast the vote(s) through e-voting (including remote e-voting) shall be made available to the members through e-mail. Members who do not receive the e-mail or whose e-mail addresses are not registered with the Company / Depository Participant(s) may generate their log-in credentials by following the instructions given below.

Manner of registration / updating e-mail addresses

Members who have not registered their e-mail addresses with the Company or their Depository Participant(s) are requested to register the same temporarily for the purpose of receiving the Notice of the AGM and Annual Report (2021-22) through the following link: https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html and complete the registration process as guided therein.

For permanent registration of e-mail addresses, members are requested to follow the below procedure:

For shares held in Physical form	1. Visit the link: https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html 2. Select the company name viz. HCL Technologies Limited. 3. Mention Folio No., Name of the Shareholder, Certificate No., PAN, Mobile Number, E-mail-ID along with a self-attested copy of your PAN Card/ Aadhar/ Valid Passport etc.
For shares held in Dematerialized form	The members holding shares in electronic mode are requested to register / update their e-mail addresses, PAN and Bank Account details with the Depository Participant where their respective demat accounts are maintained.

In case of any queries in regard to the registration process of e-mail addresses, members may contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Company at rnt.helpdesk@linkintime.co.in

For **HCL Technologies Limited**

Date: July 20, 2022
Place: Noida (U.P.)

Manish Anand
Company Secretary

Start the day right.

Mint Top of the Morning Newsletter

- The top business, economic and political news of the day
- Delivered to your inbox every morning

mint

To subscribe, scan this code or login:
livemint.com/newsletters

IndusInd Bank

CIN: L65191PN1994PLC076333 I **Regd. Office:** 2401, Gen. Thimmayya Road, Cantonment, Pune - 411 001.
Corporate Office: 8th Floor, Tower 1, One World Centre, 841, S. B. Marg, Prabhadevi (W), Mumbai - 400 013.

(₹ in Lakhs)

Q1 FY 23 Performance

Net Profit up by **61%** (Y-o-Y)

Net Interest Income up by **16%** (Y-o-Y)

CRAR up at **18.14%**

NIM up at **4.21%**

PCR consistent at **72%**

Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2022

Particulars	Consolidated			Standalone		
	Quarter ended 30.06.2022 (unaudited)	Year ended 31.03.2022 (audited)	Quarter ended 30.06.2021 (unaudited)	Quarter ended 30.06.2022 (unaudited)	Year ended 31.03.2022 (audited)	Quarter ended 30.06.2021 (unaudited)
Total income from operations	1011329	3816722	929807	1011047	3815664	929108
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	217974	643281	134147	214268	617365	128654
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	217974	643281	134147	214268	617365	128654
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	163114	480503	101611	160329	461112	97495
Equity Share Capital	77510	77466	77388	77510	77466	77388
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	4725172 (As at 31.03.2022)	4725172 (As at 31.03.2022)	4241367 (As at 31.03.2021)	4661493 (As at 31.03.2022)	4661493 (As at 31.03.2022)	4227843 (As at 31.03.2021)
Earnings Per Share (of ₹10 each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)						
- Basic	21.05	62.07	13.14	20.69	59.57	12.60
- Diluted	21.03	61.97	13.11	20.67	59.47	12.58
Net Worth	4726451	4581650	4224261	4691586	4549395	4207333
Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	-	-
Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-	-
Debt Equity Ratio	0.79	0.76	0.78	0.80	0.76	0.79
Total Debt to Total Assets	0.10	0.12	0.13	0.10	0.12	0.13

Note:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and Bank website www.indusind.com.
2. Information relating to Total Comprehensive Income and Other Comprehensive Income are not furnished as Ind AS is not yet made applicable to banks.

Mumbai
July 20, 2022

Sumant Kathpalia
Managing Director & CEO